Government has approved an Integrated Policy on oilseeds production, import, distribution and pricing to acclerate self-reliance in edible oil.

There is no proposal under the consideration of the Government for a Pulses Mission. In order to increase production of pulses, a "Pulses Production Development Programme" is being implemented in the country.

(b) The salient features of the Integrated Policy on oilseeds are as under:
— Support to farmers with technology, inputs, credit, etc. to increase oilseed production;

— Raising of PDS prices, in a phased manner to equal the cost of the domestically produced oil, based on support prices;

— Prescription of a price band for wholesale price of edible oils;

— Buffer stocking operation by National Dairy Development Board (NDDB) with domestically produced and imported stock on maintain prices within the prescribed price band; and

— Creation of a high level Empowered Committee to supervise implementation of the Integrated Policy.

दुधारु पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए निधियां

1831 **डा॰ अबरार अहमद खान:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों को दुधारु पशुओं की नस्ल सुधारने तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में कितनी धनराशि का आबंटन किया जाता है, इनमें से प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान सहायता के रूप में कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और क्या इसके परिणामस्वरूप दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार हुआ है और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए अनुदान सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की है तथा क्या यह आरोप सही है कि पंचायत स्तर पर पशु क्रय समिति द्वारा एक ही पशु को एक ही स्थान पर कई बार क्रय कर लिया जाता है; और

(ग) क्या यह संभव नहीं है कि ग्रामीणों को नकद अनुदान राशि प्रदान करने की बजाय अच्छी नस्ल के पशु प्रदान किए जांए?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) पशुओं की नस्ल में सुधार लाने और दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता देने हेतु भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध विवरण I में दी गई है (नीचे देखिये)।

देश में दूध का उत्पादन 1985-86 के 43 98 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1987-88 में 45 88 मिलियन मीटरी टन हो गया है। गत तीन वर्षों के दौरान दूध का राज्यवार उत्पादन विवरण-II में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पशुओं की नस्ल में सुधान लाने के लिए सहायता

अनुदान के रूप में राजस्थान को प्रदान की गई धनराशि 25 03 लाख रुपए है।

(ग) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत किफायती मूल्यों पर मानक गुणवत्ता वाली परिसम्पत्तियां, जो लाभानुभोगियों के लिए संतोषप्रद हों प्रदान करने और 22 चुनींदा ब्लाकों में राजसहायता और नकद ऋण का वितरण करने का प्रावधान है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक राज्य को दी गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	दी गई कुल धन राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	28.60
2	असम	19 38
3	अरुणाचल प्रदेश	24.05
4	गुजरात	33 71
5	हरियाणा	8 16
6	कर्नाटक	3.75
7	केरल	46.12
8	महाराष्ट्र	22 95
9	मेघालय	41 80
10	मणिपुर	74 80
11	नागालैण्ड	14 46
12	उड़ीसा	50.48
13	पंजाब	7 00
14	राजस्थान	25 03
15	सिक्किम	30 05
16	उत्तर प्रदेश	29 577
17	पश्चिम बंगाल	55 14
		518 677

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान दूध का राज्यवार उत्पादन

(हजार मीटर टन)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88 (अनंतिम)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2781	2783	2980
2	असम	526	539	613 1
3	अरुणाचल प्रदेश	36	37	38
4	बिहार	2702	2814*	2850
5	गुजरात	3270	3246	2997
6	गोवा	27	25	25
7	हरियाणा	2556	2624	2498
8	हिमाचल	431	459	478
9	जम्मू व कश्मीर	379	406	428
10	कर्नाटक	2013	2070	2310
11	केरल	1282	1334	1264
12	मध्य प्रदेश	2891	3069	3220
13	महाराष्ट्र	2466	2459	2657
14	मिजोरम	7*	7	12 5
15	मणिपुर	69	73	78 8
16	मेघालय	46	47	49
17	नागालैण्ड	4	401	4.8
18	उडीसा	394	4355	408
19	पजाब	4093	4168	4312
20	राजस्थान	4145	22	3911
21	सिक्किम	22*	3295	24 5
22	तमिलनाडु	3113	25	3109
23	त्रिपुरा	23	8417	26
24	उत्तर प्रदेश	8015	2597	859 5
25.	पश्चिम बंगाल	2400*	323	2664
26.	संघ शासित क्षेत्र	289		327 8
	कुल	43980	45600	45880 5

*सरकारी अनुमान